GEO IAS
It's about quality

11 July 2024

GEO Daily

Daily Current Affairs

GEO IAS

SOURCES

THE HINDU | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE | pib | PIB | live mint | THE FINANCIAL EXPRESS | ET ECONOMIC TIMES.COM

Date: 11 July 2024

Important News Articles

1. सीबीआई जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल का मुकदमा सुनवाई योग्य: सुप्रीम कोर्ट
2. तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत भरण-पोषण की हकदार हैं: सुप्रीम कोर्ट -द हिंदू
3. केंद्र ने राज्यों से शव दान के बारे में जागरूकता बढ़ाने को कहा- द हिंदू
4. लंदन में आईएमओ काउंसिल सत्र में भारत ने वैश्विक समुद्री चर्चा का नेतृत्व किया- पीआईबी
5. रूस, भारत राष्ट्रीय मुद्रा में व्यापार को आगे बढ़ाने पर सहमत - द हिंदू
6. भारत की लगभग आधी मिट्टी बाढ़ से ग्रस्त है, एक तिहाई सूखे से ग्रस्त है: अध्ययन-डाउन टू अर्थ
7. अधिकारों के मुद्दों पर काम करने वाले एनजीओ ने एफसीआरए पंजीकरण खो दिया-द हिंदू

Editorials, Gists and Explainers

8. 'हरित परिवर्तन में सहायता के लिए एमएसएमई (MSME) को प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए परिव्यय की आवश्यकता है'- द हिंदू
9. यहां तक कि छोटे-मोटे पेशे भी- द हिंदू
10. भारत महाराष्ट्र में 6 किमी गहरा गड्ढा क्यों खोद रहा है? - द हिंदू

Quick Look

1. राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार
2. जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी)
3. चन्नापटना खिलौने
4. कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र
5. विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA)

महत्वपूर्ण समाचार लेख

सामान्य अध्ययन II

1. सीबीआई जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल का मुकदमा सुनवाई योग्य: सुप्रीम कोर्ट

प्रासंगिकता: संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियाँ, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ

प्रीलिम्स टेकअवे
- सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार
- सीबीआई

समाचार:
- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल द्वारा दायर एक मूल मुकदमे की स्थिरता को बरकरार रखा, जिसमें केंद्र पर "संवैधानिक अतिरेक" का आरोप लगाया गया है और राज्य की पूर्व सहमति के बिना केंद्रीय जांच ब्यूरो को एकतरफा नियुक्त करके संघवाद का उल्लंघन किया गया है।

मुख्य बिंदु:
- सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार की प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उसे मुकदमे में गलत तरीके से प्रतिवादी बनाया गया था क्योंकि वह सीबीआई को नियंत्रित नहीं करती थी।
- "स्थापना, शक्तियों का प्रयोग, अधिकार क्षेत्र का विस्तार, डीएसपीई [अधिनियम] की देखरेख, सब कुछ भारत सरकार के पास है।
- अदालत ने केंद्र को याद दिलाया कि डीएसपीई अधिनियम अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सीबीआई जांच के लिए राज्य की पूर्व सहमति को अनिवार्य करता है।
- फैसले में कहा गया कि केंद्र सरकार सीबीआई को लेकर "बहुत चिंतित" थी, यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि केवल केंद्र द्वारा अधिसूचित अपराधों की जांच **दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) अधिनियम** के तहत सीबीआई द्वारा की जा सकती है। वह क़ानून जो प्रमुख जांच एजेंसी को नियंत्रित करता है।
- डीएसपीई अधिनियम की धारा 4 के तहत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों को छोड़कर, अन्य सभी मामलों में डीएसपीई का अधीक्षण केंद्र सरकार के पास होगा।
- संविधान के **अनुच्छेद 131** के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए मूल मुकदमे विशेष रूप से संघ और राज्यों से जुड़े विवादों से निपटते हैं,
- सॉलिसिटर जनरल ने अदालत पर पश्चिम बंगाल के मुकदमे की खूबियों पर गौर किए बिना इन प्रारंभिक आधारों पर उसे खारिज करने का दबाव डाला था।
- हालाँकि, बेंच ने बुधवार को कहा कि मुकदमा **"संघवाद के व्यापक प्रभाव से संबंधित गंभीर प्रश्न"** उठाता है।
- पश्चिम बंगाल ने विशेष तर्क दिया था कि सीबीआई ने केंद्र के निर्देशों पर काम किया था।

2. तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत भरण-पोषण की हकदार हैं: सुप्रीम कोर्ट -द हिंदू

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986।

समाचार:
- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं आपराधिक प्रक्रिया संहिता की "धर्मनिरपेक्ष" धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार हैं।

मुख्य बिंदु:
- अदालत एमिकस क्यूरी के साथ सहमत हुई, कि **सीआरपीसी की धारा 125** के धर्मनिरपेक्ष वैधानिक प्रावधान के तहत एक उपाय को मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक व्यक्तिगत कानून उपाय के अधिनियमन के आधार पर तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए बंद नहीं किया जा सकता है। .
- एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला देश में अन्य समान स्थिति वाली महिलाओं के लिए उपलब्ध भरण-पोषण के सभी अधिकारों की हकदार है।

- इसके अलावा, अदालत ने बताया कि 1986 अधिनियम की धारा 3 में एक व्यक्ति को केवल इद्दत अवधि के दौरान अपनी तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी को **"भरण-पोषण का उचित और निष्पक्ष प्रावधान"** प्रदान करने की आवश्यकता है।
- एक बार जब इद्दत अवधि समाप्त हो जाती है, तो तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भरण-पोषण देने की व्यक्तिगत कानून बाध्यता समाप्त हो जाती है।
- दूसरी ओर, धारा 125 एक पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को मासिक भरण-पोषण प्रदान करने का आदेश देती है, भले ही उसका धर्म कुछ भी हो।
- बच्चों का भरण-पोषण
- इसके अलावा, 1986 का अधिनियम एक मुस्लिम व्यक्ति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को उसके बच्चों के जन्म से केवल दो वर्ष की अवधि के लिए भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाता है।
- जबकि धारा 125 के तहत पति को अपने बच्चों के वयस्क होने तक भुगतान करने की आवश्यकता होती है।

3. केंद्र ने राज्यों से शव दान के बारे में जागरूकता बढ़ाने को कहा- द हिंदू

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- अंगदान जन जागृति अभियान

समाचार:
- देश भर के मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए मानव शवों की कमी के बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों के बाहर होने वाली मौतों की स्थिति में लोगों को शव दान करने के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की है।
- केंद्र सरकार विभिन्न अंग विफलताओं से पीड़ित लोगों के जीवन को बचाने के लिए अंग दान को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- अधिकांश मामलों में, अंग दान केवल ब्रेन स्टेम मृत रोगियों (हृदय गति रुकने से पहले) से ही संभव था।
- कई अवसरों पर यह देखा गया कि उन स्थितियों में अंग दान संभव नहीं था जहां मौतें अस्पताल के बाहर हुईं, हृदय संबंधी मौतें गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती होने से पहले हुईं और मस्तिष्क स्टेम मृत्यु प्रमाणन प्रक्रिया पूरी होने से पहले मौतें हुईं।

देहदान
- दान किए गए मानव शरीर शैक्षणिक और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं, जो चिकित्सा पेशेवरों के बेहतर शिक्षण में सहायता करते हैं।
- हमारे देश में शिक्षण के लिए आवश्यक मानव शवों की कमी है।
- राज्य स्वास्थ्य सचिवों को तदनुसार हितधारकों को निर्देश देना चाहिए, जिससे शरीर दान का विकल्प खोजा जा सके और परिवार के सदस्यों को इसके लिए प्रोत्साहित और सुविधा प्रदान की जा सके।
- जिससे चिकित्सा संस्थानों में मानव शवों की कमी को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी।

राष्ट्रव्यापी अभियान- अंगदान जन जागरूकता अभियान
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि **3 अगस्त, 2024** को भारतीय अंग दान दिवस के हिस्से के रूप में **"अंगदान जन जागरूकता अभियान"** के नाम से एक जन जागरूकता अभियान आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
- यह कहते हुए कि अंग दान और प्रत्यारोपण की सुविधा के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अंग दान एक महान कार्य है जो अंतिम चरण के अंग से पीड़ित लोगों को आशा और नया जीवन प्रदान करता है। असफलताएँ।

दाताओं और रोगियों के बीच भारी अंतर
- एक अंग दाता 8 से 9 लोगों की जान बचा सकता है। हालाँकि, जिन रोगियों को अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है और उपलब्ध अंग दाताओं के बीच एक बड़ा अंतर मौजूद है।
- इस अभियान का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली और कल्याण को बढ़ावा देकर अंग प्रत्यारोपण की मांग को कम करना, मस्तिष्क स्टेम मृत्यु और मृत अंग दान के बारे में जागरूकता फैलाना था।
- अंग दान और प्रत्यारोपण से संबंधित मिथकों और गलतफहमियों को दूर करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

4. लंदन में आईएमओ काउंसिल सत्र में भारत ने वैश्विक समुद्री चर्चा का नेतृत्व किया- पीआईबी

प्रासंगिकता: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच - उनकी संरचना, जनादेश।

प्रीलिम्स टेकअवे
- आईएमओ
- लाल सागर

समाचार:
- एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) की परिषद के 132वें सत्र में भाग ले रहा है।

मुख्य बिंदु:
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ी रुचि वाले देशों की श्रेणी में आईएमओ परिषद के एक निर्वाचित सदस्य भारत ने नाविक परित्याग के तत्काल मुद्दे पर जोर दिया।
- प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि प्रयासों के बावजूद, वर्तमान में 44 सक्रिय मामले हैं जिनमें 292 भारतीय नाविक शामिल हैं।
- ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए प्रभावी उपायों और निगरानी की आवश्यकता पर भारत के मजबूत रुख की सराहना की गई।
- नाविकों के मुद्दों को संबोधित करने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता की मान्यता में, भारत ने संयुक्त त्रिपक्षीय कार्य समूह में आईएमओ का प्रतिनिधित्व करने वाली आठ सरकारों में से एक के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है।
- यह समूह नाविकों के मुद्दों और समुद्री संचालन में मानवीय तत्वों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए समर्पित है। अन्य प्रस्तावित सदस्यों में फिलीपींस, थाईलैंड, लाइबेरिया, पनामा, ग्रीस, अमेरिका और फ्रांस शामिल हैं।
- भारत नाविक परित्याग के मुद्दे को संबोधित करने और हमारे समुद्री कार्यबल की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है।
- आईएमओ परिषद सत्र में भारत की भागीदारी अंतरराष्ट्रीय समुद्री सहयोग और नवाचार के प्रति समर्पण को रेखांकित करती है।
- सतत समुद्री परिवहन के लिए दक्षिण एशियाई उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और तकनीकी रूप से उन्नत समुद्री प्रथाओं को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व का एक प्रमाण है।
- भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने लाल सागर, अदन की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में व्यवधानों पर चिंताओं को भी संबोधित किया, जो शिपिंग और व्यापार रसद को प्रभावित कर रहे हैं।
- इसके अलावा, भारत ने सतत समुद्री परिवहन के लिए दक्षिण एशियाई उत्कृष्टता केंद्र (SACE-SMarT) के लिए अपना प्रस्ताव दोहराया।
- इस क्षेत्रीय केंद्र का लक्ष्य भारत और दक्षिण एशिया में समुद्री क्षेत्र को तकनीकी रूप से उन्नत, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और डिजिटल रूप से कुशल उद्योग में बदलना है।
- केंद्र ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने, क्षमता निर्माण और डिजिटल संक्रमण पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- आईएमओ के वैश्विक समुद्री प्रौद्योगिकी सहयोग केंद्रों (एमटीसीसी) के सहयोग से एसएसीई-एसएमआरटी विकसित करने में भारत के नेतृत्व को सतत समुद्री विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में रेखांकित किया गया।

5. रूस, भारत राष्ट्रीय मुद्रा में व्यापार को आगे बढ़ाने पर सहमत - द हिंदू

प्रासंगिकता: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करता है।

प्रीलिम्स टेकअवे
- भारत रूस संबंध
- तेल आयात

समाचार:
- भारत और रूस ने राष्ट्रीय मुद्रा निपटान के लिए एक प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है,
- भारत के प्रधान मंत्री ने "ऐतिहासिक और खेल-परिवर्तनकारी" बताई गई अपनी दो दिवसीय रूस यात्रा समाप्त करने के एक दिन बाद, यूक्रेन का समर्थन करने के लिए पश्चिमी शक्तियों की आलोचना की।

मुख्य बिंदु:

- रूसी राजदूत ने स्विट्जरलैंड में हाल ही में संपन्न शांति सम्मेलन को तमाशा बताया.
- उन्होंने कहा कि चीन के साथ रूस की दोस्ती भारत के लिए चिंता का कारण नहीं होनी चाहिए.
- रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और बहुत आशावादी परिदृश्य में हम भारत के साथ अपनी सफल और पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी जारी रखेंगे।
- संयुक्त वक्तव्य का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि हमने राष्ट्रीय मुद्रा निपटान प्रणाली की स्थापना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है, "भारतीय प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान मास्को में भारतीय और रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच चर्चा का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत किया गया।"
- श्री मोदी ने 8 और 9 जुलाई को मास्को का दौरा किया और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के साथ-साथ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आमने-सामने चर्चा की।
- चर्चा आर्थिक पहलुओं पर केंद्रित थी क्योंकि पिछले दो वर्षों में भारत के साथ रूस का व्यापार कई गुना बढ़ गया है, विशेष रूप से ऊर्जा में व्यापार के कारण जो यूक्रेन के खिलाफ "विशेष सैन्य अभियान" शुरू होने के बाद रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद तेजी से बढ़ा। फरवरी 2022 में.
- दोनों नेताओं ने उन भारतीय नागरिकों के मुद्दे पर भी चर्चा की जिन्हें धोखे से रूसी लड़ाकू बलों में शामिल किया गया और रूस-यूक्रेन सीमा पर कार्रवाई के लिए तैनात किया गया।

सामान्य अध्ययन III

6. भारत की लगभग आधी मिट्टी बाढ़ से ग्रस्त है, एक तिहाई सूखे से ग्रस्त है: अध्ययन- डाउन टू अर्थ

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन।

प्रीलिम्स टेकअवे
- मृदा नमी विसंगति

समाचार:

- गर्मी की लहरों की गंभीरता बढ़ने और हर गुजरते साल के साथ बारिश का पैटर्न और अधिक अनियमित होने के साथ, एक नए अध्ययन में पाया गया है कि भारत में कुल भूमि क्षेत्र के लगभग 32.8 प्रतिशत में 2023 में नकारात्मक मृदा नमी विसंगति (एसएमए) का अनुभव हुआ।
- इसका मतलब है कि लगभग 1.08 मिलियन वर्ग किलोमीटर (वर्ग किमी) सूखे के तनाव की चपेट में है।

भारत की मिट्टी की नमी की चुनौतियाँ: एक विघटन

असमान जल वितरण:

- **सूखे का खतरा:** भारत की एक-तिहाई (32.8%) भूमि, लगभग 1.08 मिलियन वर्ग किमी, औसत से कम मिट्टी की नमी (नकारात्मक विसंगतियों) के कारण सूखे के खतरे का सामना करती है।
- **बाढ़ की संभावना:** देश का लगभग आधा (47.7%) हिस्सा 1.57 मिलियन वर्ग किमी में सामान्य से अधिक नमी वाली स्थितियों (सकारात्मक विसंगतियों) का अनुभव करता है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है।

मौसमी बदलाव:

मानसून (जून-सितंबर):

- पंजाब में मिट्टी में पर्याप्त नमी है, जिससे फसल की स्वस्थ वृद्धि को बढ़ावा मिला और संभावित रूप से बाढ़ से बचा जा सका।
- ओडिशा की औसत नमी का स्तर पंजाब से जल प्रबंधन रणनीतियों को सीखकर बेहतर कृषि उत्पादन की संभावना का सुझाव देता है।
- बिहार और झारखंड शुष्क मिट्टी से जूझ रहे हैं, जिससे बेहतर सिंचाई और जल संरक्षण प्रथाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

राज्य-वार निहितार्थ

- पंजाब: सकारात्मक मिट्टी की नमी विसंगतियों से लाभ, मजबूत कृषि का समर्थन।
- ओडिशा: विशिष्ट अवधियों के दौरान नकारात्मक एसएमए के साथ चुनौतियों का सामना करता है, जो अन्य राज्यों से कुशल सिंचाई प्रथाओं को अपनाने का सुझाव देता है।
- बिहार, झारखंड: सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए बेहतर जल संरक्षण और सिंचाई तकनीकों की आवश्यकता है।
- महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश: मिट्टी की नमी के स्तर में परिवर्तनशीलता देखी गई, जिससे स्थिर जल प्रबंधन नीतियों की आवश्यकता हुई।
- आंध्र प्रदेश, केरल: मिट्टी की नमी की बदलती स्थितियों के कारण अनुकूलित जल प्रबंधन योजनाओं की आवश्यकता है।

नीति सिफारिशों

- क्षेत्रीय मिट्टी की नमी की स्थिति के आधार पर अनुरूप जल प्रबंधन नीतियां विकसित करने की आवश्यकता है।
- राज्य को कमी वाले क्षेत्रों में सूखा प्रबंधन योजनाओं और अधिशेष नमी वाले क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना चाहिए।
- किसानों को वास्तविक समय डेटा के लिए रिमोट सेंसिंग और ग्राउंड-आधारित सेंसर का उपयोग करके उन्नत मिट्टी की नमी निगरानी प्रणालियों में निवेश करना चाहिए।
- पंजाब में औसत से ऊपर नमी बनी रही, जबकि ओडिशा में थोड़ी कमी का सामना करना पड़ा। यह दोनों राज्यों के बीच सहयोगात्मक जल प्रबंधन रणनीतियों से संभावित लाभ का सुझाव देता है।

7. अधिकारों के मुद्दों पर काम करने वाले एनजीओ ने एफसीआरए पंजीकरण खो दिया- द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों की योजना, जुटाव, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे

- विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम

समाचार:

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैर-लाभकारी वित्तीय जवाबदेही केंद्र (सीएफए) की मूल इकाई का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण रद्द कर दिया।
- एनजीओ वित्तीय संस्थानों की भूमिका और विकास, मानवाधिकार और पर्यावरण पर उनके प्रभाव की निगरानी और आलोचनात्मक विश्लेषण करता है।

मुख्य बिंदु-

- हाल की एक रिपोर्ट में, सीएफए ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अदानी समूह द्वारा संचालित एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्वीकृत अतिरिक्त परियोजनाएं "पर्यावरणीय खतरों को बढ़ाएंगी और लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ाएंगी, साथ ही पर्यावरण को प्रदूषित करेंगी और "पारिस्थितिकी" गिरावट में तेजी लाएंगी।
- इससे पहले जनवरी में, मंत्रालय ने नई दिल्ली में अग्रणी **सार्वजनिक नीति अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर)** का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया था।
- 2015 से, 16,000 से अधिक गैर सरकारी संगठनों का एफसीआरए पंजीकरण "उल्लंघन" के कारण रद्द कर दिया गया है।
- देश में 15,946 एफसीआरए-पंजीकृत एनजीओ सक्रिय थे। लगभग 6,000 एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण 1 जनवरी, 2022 से बंद हो गया था क्योंकि मंत्रालय ने या तो उनके आवेदन को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था या एनजीओ ने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था।

एडिटोरियल, जिस्ट, एक्सप्लेनेर

8. 'हरित परिवर्तन में सहायता के लिए एमएसएमई (MSME) को प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए परिव्यय की आवश्यकता है'- द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

समाचार:

- केंद्रीय लघु,मध्यम और सूक्ष्म उद्योग मंत्री ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए फोकस क्षेत्रों के रूप में **छह स्तंभों की पहचान** की गई है - ऋण तक औपचारिकीकरण और पहुंच, बाजार और ई-कॉमर्स अपनाने तक पहुंच में वृद्धि, आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च उत्पादकता, उन्नत कौशल स्तर और सेवा क्षेत्र में डिजिटलीकरण, वैश्वीकरण के लिए खादी, ग्राम और कॉयर उद्योग को समर्थन, और उद्यम निर्माण के माध्यम से महिलाओं और कारीगरों का सशक्तिकरण।

प्रसंग:

- आगामी बजट में विकास को बढ़ावा देने, मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने, रोजगार पैदा करने, एमएसएमई को बढ़ावा देने, व्यापार करने में आसानी का समर्थन करने और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए संतुलन बनाना चाहिए।
- दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए वह है- सतत आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, खासकर औद्योगिक समूहों में।

रोजगार बढ़ाना

- सरकार ने पिछले छह वर्षों में निर्यात में 8.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज करके अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है, जो वित्त वर्ष 2018 में 478 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2014 में 778 बिलियन डॉलर हो गया है।
- अब हमारा लक्ष्य वित्त वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का है, जिसके लिए 14.4% सीएजीआर की आवश्यकता है।
- वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति में यह एक चुनौती है लेकिन पहुंच के दायरे में है। इसके लिए एक सक्षम और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करके निर्यातकों और एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देने की आवश्यकता है।
- वर्तमान स्थिति में एमएसएमई को बढ़ावा देने का महत्व अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और एक प्रमुख रोजगार उत्पन्न करने वाला है।
- मौजूदा चुनौतीपूर्ण स्थिति में इस क्षेत्र को बनाए रखने और बढ़ने के लिए, एमएसएमई की एक मजबूत मांग यह है कि गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) की समयसीमा को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन किया जाए।
- इससे इस क्षेत्र को राहत मिलेगी क्योंकि कई एमएसएमई इस वजह से संघर्ष कर रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को भी नया रूप दिया जाना चाहिए।
- ब्याज समानीकरण योजना निर्यात का जोरदार समर्थन करती है। इस योजना को पांच साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। पिछले दो वर्षों में रेपो दर में 4.4% से 6.5% की वृद्धि के परिणामस्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि के कारण, एमएसएमई में निर्माताओं के लिए छूट दरों को सभी 410 टैरिफ लाइनों के संबंध में 3% से 5% और 2% से 3% तक बहाल किया जा सकता है।
- कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए, जिसमें एमएसएमई का वर्चस्व है, और निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट [RoDTEP] और राज्य और केंद्रीय करों और लेवी में छूट [ROSCTL] योजनाओं को इस क्षेत्र के लिए अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।
- बजट में अगले दो वर्षों के लिए एमएसएमई निर्यातकों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को फिर से शुरू करने पर विचार करना चाहिए। इससे अधिकांश एमएसएमई इकाइयों को उनके निर्यात में सहायता मिली।
- एमएसएमई जॉब वर्क के भुगतान की समय सीमा मौजूदा 45 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन की जानी चाहिए क्योंकि आरबीआई निर्यात आय की वसूली के लिए 180 दिनों की समय सीमा की अनुमति देता है।
- जब तक निर्यातकों को खरीदारों से भुगतान नहीं मिल जाता, तब तक एमएसएमई श्रमिकों को भुगतान करना मुश्किल होगा, जिससे निर्यातकों के लिए फंड प्रवाह संबंधी समस्याएं पैदा होंगी।
- कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए, पीएलआई योजना के तहत निवेश सीमा को घटाकर ₹25 करोड़ और टर्नओवर की सीमा को घटाकर ₹70 करोड़ किया जाना चाहिए। इससे एमएसएमई निर्यातकों को अपनी प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी।

हरित परिवर्तन, अनुसंधान एवं विकास

- चिंता का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जलवायु परिवर्तन है। इससे एमएसएमई पर गंभीर असर पड़ा है। इसलिए हरित परिवर्तन का प्रयास करने और हरित संसाधनों के साथ विकास को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई के लिए अधिक सॉफ्ट फंड उपलब्ध कराए जाने चाहिए। **तिरुपुर जैसे एमएसएमई क्लस्टर इस समर्थन से महत्वपूर्ण निर्यात क्षमता का लाभ उठा सकते हैं।**
- निर्यात को बनाए रखने के लिए अनुसंधान विकास और नवाचार महत्वपूर्ण हैं। विश्व स्तर पर R&D को प्रोत्साहन दिया जाता है और 38 OECD देशों में से 35 देश R&D व्यय पर या तो कम कर या अधिक कटौती प्रदान करते हैं।
- हम उम्मीद करते हैं कि धारा 35(2एबी) के तहत भारित कर कटौती को 300% तक बढ़ाया जा सकता है और धारा 35(2एबी) के तहत लाभ सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), साझेदारी फर्मों और मालिकाना फर्मों तक भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एमएसएमई इकाइयां बड़े पैमाने पर गिरती हैं। इन श्रेणियों में.
- बुनियादी ढांचे के निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए धन उपलब्ध कराने वाली योजनाओं के साथ, एमएसएमई क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए और भी अधिक योगदान करने में सक्षम होगा।

9. यहां तक कि छोटे-मोटे पेशे भी- द हिंदू

प्रासंगिकता: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्रसंग:

- गिग श्रमिकों को अपने कर्मचारी की स्थिति पर एक व्यापक राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है
- भारत के गिग श्रमिकों के लिए, जो संख्या में बढ़ रहे हैं, लेकिन अनियमित श्रम पूल के किनारे पर अनिश्चित रूप से बैठे हैं, कर्नाटक प्लेटफ़ॉर्म-आधारित **गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2024,** एक स्वागत योग्य राहत प्रदान करता है, लेकिन अभी भी कम है। उन्हें कर्मचारी होने की सुरक्षा प्रदान करना।

गिग आय	**कानून**
• जब एक दशक पहले राइड-शेयरिंग और फूड डिलीवरी ऐप्स के सौजन्य से ऐप-आधारित गिग वर्क पेश किया गया था, तो 'कर्मचारी' शब्द की अनुपस्थिति को वास्तव में एक सकारात्मक के रूप में देखा गया था; कथित तौर पर इसने 'साझेदारों' को अपनी स्वायत्तता बनाए रखने और कठोर समय के साथ अनुबंध में बंधे बिना अच्छा पैसा कमाने का मौका दिया। • वह भ्रम जल्द ही दूर हो गया क्योंकि आय कम हो गई और काम के घंटे बढ़ गए, और औपचारिक 'कर्मचारी' स्थिति की कमी ने श्रमिकों को सुरक्षा जाल या सरकारी विनियमन के अभाव में एग्रीगेटर और सर्व-शक्तिशाली एल्गोरिदम की दया पर छोड़ दिया। • इसके बावजूद गिग इकॉनमी बढ़ रही है. नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, दशक की शुरुआत में भारत में 77 लाख गिग श्रमिक थे, और 2029-30 तक, उनकी आय का 4.1% और गैर-कृषि कार्यबल का 6.7% होने का अनुमान है। • एक अधिकार-आधारित कानून, मसौदा विधेयक का उद्देश्य मनमाने ढंग से बर्खास्तगी को रोकना, मानव शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना और स्वचालित निगरानी और एल्गोरिदम-आधारित भुगतान की अपारदर्शी उलझन में अधिक पारदर्शिता लाना है।	• यह केंद्र सरकार की **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** से एक कदम ऊपर है। कर्नाटक का कानून एक कल्याण बोर्ड और फंड के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करता है, जिसमें सरकार और एग्रीगेटर का योगदान होता है, या तो ऐप पर प्रत्येक लेनदेन में कटौती के माध्यम से, या राज्य में प्लेटफ़ॉर्म के कारोबार के प्रतिशत के रूप में। • यह देखते हुए कि इन प्लेटफार्मों की मालिक कई कंपनियां न्यूनतम लाभ की रिपोर्ट करती हैं, श्रमिक संघों ने सही मांग की है कि प्रत्येक लेनदेन पर कल्याण शुल्क को उपकर के रूप में लिया जाए। • संशयवादी अन्य असंगठित क्षेत्र कल्याण बोर्डों की मृतप्राय प्रकृति पर ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसे बोर्ड के साथ अनिवार्य पंजीकरण का एक फायदा यह है कि यह गिग श्रमिकों को कानून की नजरों में दिखाई देगा। • कर्नाटक सरकार का लक्ष्य विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक को लागू करना है, और उसे जल्दी से नियम बनाने होंगे और कल्याण बोर्ड की स्थापना करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानून वर्ष के अंत से पहले लागू हो। • राजस्थान में भी इसी तरह का कानून पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसे प्रभावी रूप से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। • राष्ट्रीय स्तर पर, न केवल न्यूनतम मजदूरी, उचित काम के घंटे और शर्तें और मजबूत सामाजिक सुरक्षा निर्धारित करने के लिए बल्कि गिग श्रमिकों को 'कर्मचारी' की प्रतिष्ठित स्थिति प्रदान करने के लिए भी व्यापक कानून की आवश्यकता है।

10. भारत महाराष्ट्र में 6 किमी गहरा गड्ढा क्यों खोद रहा है? - द हिंदू

प्रासंगिकता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और उनके अनुप्रयोग और रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभाव।

प्रसंग:

- वैज्ञानिकों के पास अभी तक यह अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है कि भूकंप कब और कहाँ आएगा।
- हम जानते हैं कि टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर शक्तिशाली भूकंप, जिनकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.5 से अधिक होती है, लगभग निश्चित रूप से बुनियादी ढांचे और जीवन के गंभीर नुकसान से जुड़े होते हैं।
- समुद्र में, ये भूवैज्ञानिक घटनाएँ सुनामी को जन्म देती हैं। हालाँकि, प्लेट के आंतरिक भाग में आने वाले अधिक छोटे भूकंपों की भविष्यवाणी करना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि वे कम से कम अपेक्षित स्थानों पर आते हैं और घनी आबादी वाले आवासों पर हमला कर सकते हैं।
- यही कारण है कि वैज्ञानिक गहरी ड्रिलिंग पृथ्वी विज्ञान में प्रगति के लिए एक अनिवार्य उपकरण है।

वैज्ञानिक गहरी ड्रिलिंग क्या है?

- वैज्ञानिक **डीप-ड्रिलिंग** पृथ्वी की पपड़ी के गहरे हिस्सों का विश्लेषण करने के लिए रणनीतिक रूप से बोरहोल खोदने का उद्यम है।
- यह भूकंपों का अध्ययन करने के अवसर और पहुंच प्रदान करता है और ग्रह के इतिहास, चट्टान के प्रकार, ऊर्जा संसाधनों, जीवन रूपों, जलवायु परिवर्तन पैटर्न और बहुत कुछ के बारे में हमारी समझ का विस्तार करता है।

गहरे ड्रिलिंग मिशन के लाभ	वैज्ञानिकों ने क्या पाया है?
• भूकंप का अध्ययन करना चुनौतीपूर्ण है। सतह-स्तरीय अवलोकन उनका पूरा अर्थ नहीं निकाल सकते। • कोयना में बार-बार आने वाले भूकंप मानसून और मानसून के बाद की अवधि के दौरान बांध की लोडिंग और अनलोडिंग के साथ समकालिक होते हैं, जो भूकंप के बारे में हमारी समझ को व्यापक बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। • वैज्ञानिक रूप से ड्रिल किए गए बोरहोल प्रत्यक्ष, अद्वितीय सीटू प्रयोगों और अवलोकनों का केंद्र हो सकते हैं और किसी क्षेत्र की गलती रेखाओं और भूकंपीय व्यवहार की निगरानी कर सकते हैं। • वे पृथ्वी की पपड़ी की संरचना, संरचना और प्रक्रियाओं का सटीक और मौलिक ज्ञान भी प्रदान करते हैं, और सतह के अध्ययन के आधार पर मॉडल को मान्य करने में मदद करते हैं। • इस प्रकार, यह भू-खतरों और भू-संसाधनों से संबंधित कई सामाजिक समस्याओं की जानकारी दे सकता है। • वैज्ञानिक गहरी-ड्रिलिंग में निवेश करने से वैज्ञानिक जानकारी और तकनीकी नवाचार का विस्तार करने में भी मदद मिल सकती है, खासकर भूकंप विज्ञान (भूकंप का अध्ययन) में। • यह ड्रिलिंग, अवलोकन, डेटा विश्लेषण, सेंसर आदि के लिए उपकरणों और उपकरणों के विकास को भी प्रोत्साहित कर सकता है। • पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक गहरी ड्रिलिंग सबसे अच्छा उपकरण है। अन्य तरीकों में भूकंपीय तरंग गति, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र और निकट सतह से विद्युत चालकता का भूभौतिकीय माप शामिल है। वैज्ञानिक गहरे भूमिगत से सतह पर लाए गए क्रस्ट के टुकड़ों की भी जांच कर सकते हैं। • लेकिन वैज्ञानिक गहरी-ड्रिलिंग सबसे विश्वसनीय विधि बनी हुई है क्योंकि यह प्रत्यक्ष (सीटू में) और निकट-स्रोत माप प्राप्त करने में मदद करती है। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक गर्म, अंधेरा, उच्च दबाव वाला क्षेत्र है जो लंबे और निरंतर संचालन में बाधा डालता है। • भूकंपों के अलावा, ऐसा इसलिए है क्योंकि कई सतही घटनाएं, पानी और हवा की संरचना, उनकी उपलब्धता, और जलवायु-प्रभावित घटनाओं के साथ परिणामी बातचीत पृथ्वी की पपड़ी के अंदर क्या होता है, उससे जुड़ी हुई हैं।	• पायलट ड्रिलिंग मिशन सफल रहा और इससे उपसतह भूवैज्ञानिक पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण नई जानकारी प्राप्त हुई है। • एक के लिए, इसने 1.2-किमी मोटी, 65 मिलियन वर्ष पुराने डेक्कन ट्रैप लावा प्रवाह का खुलासा किया, और उनके नीचे 2,500-2,700 मिलियन वर्ष पुरानी ग्रेनाइटिक बेसमेंट चट्टानें थीं। • 3 किमी की गहराई से कोर नमूनों और स्थितियों के डाउनहोल माप ने चट्टानों के भौतिक और यांत्रिक गुणों, गठन तरल पदार्थ और गैसों की रासायनिक और समस्थानिक संरचना, तापमान और तनाव शासन, और फ्रैक्चर अभिविन्यास के बारे में नई जानकारी भी प्रदान की है। • उम्मीद है कि ये प्रयोग कई वर्षों तक उपयोगी रहेंगे, विशेषकर विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में बार-बार आने वाले भूकंपों के कारणों को समझने के लिए। • संक्षेप में, कोयना अभ्यास भारत के लिए वैज्ञानिक गहरी ड्रिलिंग में एक मजबूत आधार स्थापित कर रहा है। इसके पाठ भविष्य के गहन-ड्रिलिंग प्रयोगों की जानकारी देंगे और कई तरीकों से अकादमिक ज्ञान का विस्तार करेंगे।

फैक्ट फटाफट

1. राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार

- यह पशुधन और डेयरी क्षेत्र के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है।
- इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में काम करने वाले स्वदेशी पशुओं को पालने वाले किसानों, एआई तकनीशियनों और डेयरी सहकारी समितियों / दूध उत्पादक कंपनी / डेयरी किसान उत्पादक संगठनों जैसे सभी व्यक्तियों को पहचानना और प्रोत्साहित करना है।
- यह पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, अर्थात्, स्वदेशी मवेशी/भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एआईटी) और सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी/दूध उत्पादक कंपनी/डेयरी किसान उत्पादक संगठन)

2. जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी)

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है।
- इसकी स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा नीति निर्माताओं को जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार, इसके प्रभावों और भविष्य के जोखिमों और अनुकूलन और शमन के विकल्पों के नियमित आकलन प्रदान करने के लिए की गई थी।
- आईपीसीसी के आकलन सभी स्तरों पर सरकारों को जलवायु-संबंधी नीतियां विकसित करने के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं, और वे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन - जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) में बातचीत का आधार बनते हैं।

3. चन्नापटना खिलौने

- चन्नापटना खिलौने लकड़ी के खिलौनों और गुड़ियों का एक विशेष रूप हैं जिनका निर्माण कर्नाटक के रामनगर जिले के चन्नापटना शहर में किया जाता है।
- चन्नापटना को गोम्बेगाला ऊरू (खिलौना-शहर) के नाम से भी जाना जाता है।
- चन्नापटना खिलौनों का इतिहास 18वीं शताब्दी में मैसूर साम्राज्य के पूर्व शासक टीपू सुल्तान के शासनकाल से खोजा जा सकता है।
- किंवदंती के अनुसार, टीपू सुल्तान फ़ारसी कारीगरों की शिल्प कौशल से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें स्थानीय कारीगरों को खिलौना बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया।
- इसने चन्नापटना खिलौना उद्योग की शुरुआत को चिह्नित किया, जो तब से फला-फूला है।

4. कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र

- भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है।
- मार्च 2002 में रूस की तकनीकी सहायता से निर्माण शुरू हुआ।
- पहली बिजली इकाई फरवरी 2016 से चालू है, जो 1,000 मेगावाट की क्षमता पर काम कर रही है।
- 2027 तक पूर्ण परिचालन क्षमता की उम्मीद
- परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली का पांचवां सबसे बड़ा स्रोत है, जो देश की कुल बिजली उत्पादन में लगभग 2% का योगदान देता है।

- भारत के पास वर्तमान में देश भर में 7 बिजली संयंत्रों में 22 से अधिक परमाणु रिएक्टर हैं, जो कुल मिलाकर 6,780 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं।

5. विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA)

- यह भारत के भीतर गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों को कुछ व्यक्तियों या संघों द्वारा प्रदान किए गए विदेशी योगदान (विशेष रूप से मौद्रिक दान) को विनियमित करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून है।
- अधिनियम, अपने समेकित रूप में, मूल रूप से 1976 में पारित किया गया था और 2010 में प्रमुख रूप से संशोधित किया गया था।
- अधिनियम का उद्देश्य विदेशी संगठनों को सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक गलत उद्देश्यों और गतिविधियों के लिए भारत में चुनावी राजनीति, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक चर्चाओं को प्रभावित करने से रोकना है।
- यह अधिनियम गृह मंत्रालय (एमएचए) के दायरे में आता है।

प्रीलिम्स ट्रैक

Q1. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सीबीआई की स्थापना 1963 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
2. सीबीआई को अपनी शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से प्राप्त होती हैं।
3. सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति द्वारा की जाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3

Q2. भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. "तलाक-ए-बिदह" एक ही बैठक में दिए गए तत्काल और अपरिवर्तनीय तलाक को संदर्भित करता है।
2. इस्लामी कानून में मेहर का तात्पर्य उस अनिवार्य उपहार या वित्तीय निपटान से है जो एक पति को शादी के समय अपनी पत्नी को देना होता है।
3. भारत में शरिया अदालतों को मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल एक
B. सिर्फ दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

Q3. भारत में रक्तदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में रक्तदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
2. एक व्यक्ति हर 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है।
3. रक्तदान को सुरक्षित माना जाता है और रक्तदान से बीमारियाँ होने का खतरा न्यूनतम होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3

Q4. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आईएमओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है।
2. IMO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
3. आईएमओ का प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षा, पर्यावरण संबंधी चिंताओं, कानूनी मामलों और समुद्री सुरक्षा सहित शिपिंग के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा विकसित करना और बनाए रखना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3

Q5. रूस के भूगोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रूस की सीमा 16 देशों के साथ लगती है।
2. रूस में यूराल पर्वत को यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा माना जाता है।
3. रूस में स्थित बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3

Q6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन I: मिट्टी में 39 इंच की गहराई तक पानी और नमी को जड़ क्षेत्र की नमी कहा जाता है

कथन II: जड़ क्षेत्र की नमी बारिश पर निर्भर नहीं करती है

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
B. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
C. कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है
D. कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

Q7. विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उल्लंघन के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एफसीआरए पंजीकरण को अधिकतम 180 दिनों की प्रारंभिक अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है।
2. एफसीआरए संगठनों को समसामयिक मामलों के कार्यक्रमों पर रिपोर्ट प्रकाशित करने से रोकता है।
3. किसी संगठन के लिए एफसीआरए पंजीकरण रद्द करना गहन सुनवाई और अपना मामला पेश करने के अवसर के अधीन है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

A. केवल एक
B. सिर्फ दो
C. सभी तीन
D. कोई नहीं

Q8. भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और संबंधित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उद्योग आधार मेमोरेंडम (यूएएम) लॉन्च किया।
2. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का लक्ष्य तीन उत्पादों: शिशु, किशोर और तरुण के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
3. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) एमएसएमई को संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

Q9. गिग इकॉनमी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. गिग अर्थव्यवस्था एक श्रम बाजार को संदर्भित करती है जो स्थायी नौकरियों के विपरीत अल्पकालिक अनुबंधों या फ्रीलांस काम द्वारा विशेषता होती है।
2. गिग श्रमिक पारंपरिक कर्मचारियों के समान स्वास्थ्य बीमा और सेवानिवृत्ति योजनाओं जैसे समान रोजगार लाभों के हकदार हैं।
3. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और प्रौद्योगिकी के उदय ने गिग अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3

Q10. भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, उपरिकेंद्र कहलाता है।
2. रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है।
3. रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर बेसिन का एक क्षेत्र है जो अपने उच्च भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि के लिए जाना जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

प्रीलिम्स ट्रैक उत्तर

उत्तर : 1 विकल्प D सही है

स्पष्टीकरण:

- सीबीआई की स्थापना वास्तव में 1963 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। **कथन 1 सही है**
- सीबीआई को अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से प्राप्त होती हैं। **कथन 2 सही है**
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार, सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की एक समिति द्वारा की जाती है, न कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का सीधे तौर पर **कथन 3 सही है**

उत्तर : 2 विकल्प B सही है

स्पष्टीकरण

- तलाक-ए-बिदह, या एक बार में तीन तलाक, मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक प्रचलित प्रथा थी जहां एक पति एक ही सत्र में तीन बार तलाक कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था। हालाँकि, 2019 में, भारत सरकार ने मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम लागू किया, जिससे इस प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया। **अतः, कथन 1 सही है**
- मेहर वास्तव में एक अनिवार्य भुगतान या उपहार है जो एक पति को इस्लामी कानून में शादी के समय अपनी पत्नी को देना होता है। इसका उद्देश्य पत्नी को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है और इसकी राशि पर विवाह अनुबंध के दौरान सहमति होती है। **अतः, कथन 2 सही है**
- भारत में शरिया अदालतें, जिन्हें दार-उल-क़ज़ा के नाम से भी जाना जाता है, को कानूनी मंजूरी नहीं है और उनके फैसले बाध्यकारी नहीं हैं। पारिवारिक मामलों सहित भारतीय कानूनी प्रणाली, भारतीय कानूनों द्वारा शासित होती है। हालाँकि, व्यक्ति विवाद समाधान के लिए धार्मिक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अंतिम कानूनी अधिकार भारतीय न्यायपालिका के पास है। **इसलिए, कथन 3 गलत है**

उत्तर : 3 विकल्प D सही है

स्पष्टीकरण:

- भारत में रक्तदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु वास्तव में 18 वर्ष है। **कथन 1 सही है**
- एक व्यक्ति आमतौर पर पुरुषों के लिए हर 3 महीने (12 सप्ताह) में एक बार और महिलाओं के लिए हर 4 महीने (16 सप्ताह) में एक बार रक्तदान कर सकता है। **कथन 2 सही है**
- रक्तदान को आम तौर पर सुरक्षित माना जाता है, और अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएँ रक्तदान के माध्यम से बीमारियों के होने का न्यूनतम जोखिम सुनिश्चित करती हैं। **कथन 3 सही है**

उत्तर : 4 विकल्प B सही है

स्पष्टीकरण:

- आईएमओ वास्तव में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। **कथन 1 सही है**
- IMO का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, न कि जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। **कथन 2 गलत है**
- आईएमओ का प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षा, पर्यावरण संबंधी चिंताओं, कानूनी मामलों और समुद्री सुरक्षा सहित शिपिंग के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा विकसित करना और बनाए रखना है। **कथन 3 सही है**

उत्तर : 5 विकल्प C सही है

स्पष्टीकरण:

- रूस की सीमा 16 देशों के साथ नहीं, बल्कि 14 देशों के साथ लगती है। **कथन 1 गलत है**
- रूस में यूराल पर्वत को यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा माना जाता है। **कथन 2 सही है**
- रूस में स्थित बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। **कथन 3 सही है**

उत्तर : 6 विकल्प C सही है

स्पष्टीकरण

- जड़ क्षेत्र की नमी मिट्टी में 39 इंच की गहराई तक पानी और नमी को जड़ क्षेत्र की नमी कहा जाता है। बारिश के अभाव में जलभरों को सूखे से उबरने में काफी समय लगता है। अतः, **कथन 1 सही है।**

- जलभृत मिट्टी और चट्टानों के माध्यम से रिसने के लिए सतह की नमी पर निर्भर करते हैं। जब बारिश नहीं होती और सतह पर नमी नहीं होती, तो जड़ क्षेत्र की नमी पूरी तरह से गायब हो सकती है। यह अंततः मिट्टी को पेड़-पौधों के लिए अनुपयुक्त बना देगा। इसलिए, **कथन 2 गलत है।**

उत्तर : 7 विकल्प A सही है

स्पष्टीकरण

- उल्लंघन के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एफसीआरए पंजीकरण को निलंबित किया जा सकता है। प्रारंभिक निलंबन अवधि अधिकतम 180 दिनों के लिए है। यह सरकार को कथित उल्लंघनों के मामले में किसी संगठन की विदेशी योगदान प्राप्त करने की क्षमता को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के लिए एक उपकरण प्रदान करता है। अतः, **कथन 1 सही है**
- एफसीआरए संगठनों को समसामयिक मामलों के कार्यक्रमों पर रिपोर्ट प्रकाशित करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है। यह अधिनियम मुख्य रूप से विदेशी योगदान की स्वीकृति और उपयोग को नियंत्रित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक नहीं हैं। इसलिए, **कथन 2 गलत है**
- एफसीआरए पंजीकरण रद्द करना हमेशा गहन सुनवाई और मामले को प्रस्तुत करने के अवसर के अधीन नहीं होता है। कुछ मामलों में, संगठन को सुनवाई के पर्याप्त अवसर के बिना रद्दीकरण हो सकता है, जिससे उचित प्रक्रिया के बारे में चिंताएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए, **कथन 3 गलत है**

उत्तर : 8 विकल्प D सही है

स्पष्टीकरण:

- एमएसएमई मंत्रालय ने वास्तव में एमएसएमई के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उद्योग आधार मेमोरेंडम (यूएएम) लॉन्च किया। **कथन 1 सही है**
- प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का लक्ष्य तीन उत्पादों के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है: शिशु (₹50,000 तक का ऋण), किशोर (₹50,001 से ₹5 लाख तक का ऋण), और तरूण (₹5 लाख तक का ऋण)। से ₹10 लाख)। **कथन 2 सही है**
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) एमएसएमई को संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करता है। **कथन 3 सही है**

उत्तर : 9 विकल्प B सही है

स्पष्टीकरण:

- गिग अर्थव्यवस्था वास्तव में एक श्रम बाजार को संदर्भित करती है जो स्थायी नौकरियों के विपरीत अल्पकालिक अनुबंधों या फ्रीलांस काम द्वारा विशेषता है। **कथन 1 सही है**
- गिग श्रमिकों को आमतौर पर पारंपरिक कर्मचारियों के समान स्वास्थ्य बीमा और सेवानिवृत्ति योजनाओं जैसे रोजगार लाभ नहीं मिलते हैं; उन्हें अक्सर ऐसे लाभों का अभाव होता है। **कथन 2 ग़लत है**
- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और प्रौद्योगिकी के उदय ने गिग अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे अधिक लोगों को गिग काम ढूंढने में सक्षम बनाया गया है। **कथन 3 सही है**

उत्तर : 10 विकल्प B सही है

स्पष्टीकरण:

- पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां भूकंप उत्पन्न होता है, उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहा जाता है, उपरिकेंद्र नहीं। भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह पर फोकस के ठीक ऊपर स्थित बिंदु है। **कथन 1 ग़लत है**
- रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है। **कथन 2 सही है**
- रिंग ऑफ फायर वास्तव में प्रशांत महासागर बेसिन का एक क्षेत्र है जो अपने उच्च भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि के लिए जाना जाता है। **कथन 3 सही है**

GEO IAS

It's about quality

ABOUT US

GEO IAS is the best institute for civil services in India for providing top quality teaching and materials, offering you most optimum path for your success in Civil Services exam. Our aim is to provide quality training with an affordable fee structure. Our uniquely designed course make us the best institute for UPSC to crack the exam in one go. We have a dedicated team of experienced and young teachers and counsellors who make sure that every student who joins the institute, must get customized way of preparation which matches with student's learning style.
The only institute of UPSC in India which has 3 AI enabled Mobile apps. We believe in Smart way of teaching and learning. The classes are available in offline as well as in online mode. We take the help of animation so that you may visualize the lectures. Unlimited tests for prelims and mains with solution in both form (Hard copy and soft copy). We have the set of 15 lac mcqs on each topic. We provide daily news analysis, Highlighted news paper and links of important Sansad TV shows. The institute has best success rate with more than 230 students have cleared the exam. HIGHEST RATED INSTITUTE as per GOOGLE, SULEKHA and JUST DIAL and the magazine on civil services

+91-9477560001 /002/005

BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | HEAD OFFICE: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

info@geoias.com

www.geoias.com